International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 9, Issue 11, November 2022
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

भारत में आपराधिक संकेत में निजी रक्षा के अधिकार का अध्ययन

SUMAN DEVI
RESEARCH SCHOLAR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR
DR. VINOD KUMAR SHARMA
ASSOCIATE PROFESSOR SUNRISE UNIVERSITY ALWAR

सारांश

इस अध्ययन का उद्देश्य निजी रक्षा अनिवार्य रूप से रक्षा या आत्मरक्षा में से एक है ; और आत्मरक्षा के कारण स्वयं को होने वाली क्षति, दंड का अधिकार नहीं, रक्षा के लिए वैध रूप से आवश्यक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा , अपराध करने के प्रयास या खतरे से शरीर को होने वाले खतरे के पर्याप्त आकलन की शुरुआत और अस्तित्व के साथ, सही सह-समाप्ति होती है। यह केवल किसी खतरे के विरुद्ध वास्तविक, वर्तमान और आसन्न का उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन परिस्थितियों में अपना अधिकार रखने और कायरों की तरह भागने का अधिकार नहीं है। उसके पास हमलावर पर पलटवार करने का हर कारण है जो उसे पहुंचाई गई चोट के अनुपात में नहीं हो सकता है। गोपनीयता का मूल सिद्धांत यह है कि इस मामले में एक व्यक्ति खुद को या अपनी संपत्ति की रक्षा करने का हकदार है जब कोई व्यक्ति या उसकी संपत्ति खतरे में हो और राज्य मशीनरी सहायता नहीं दी जाती है। व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया बल, रोके जाने वाले नुकसान के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिवादी को प्राप्त चोटें, अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोटें , उसकी सुरक्षा का आसन्न खतरा और यह तथ्य कि अभियुक्त के पास सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का समय था, ये सभी प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें यह स्थापित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या कोई निजी बचाव का अधिकार मौजूद है या नहीं. व्यक्तिगत रक्षा बचाव में निजी साधनों के माध्यम से हमलावर के खिलाफ दूसरों के व्यक्तियों और संपत्तियों की रक्षा करने का अधिकार ही शामिल नहीं है। प्रत्येक नागरिक समाज के लिए इस अधिकार को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है और उस देश के विधायी प्रावधानों में इसे स्थान दिया गया है। कानून की डिग्री और

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

संरचना विभिन्न कानूनी प्रणालियों में भिन्न होती है , लेकिन लगभग हर कानूनी प्रणाली का एक या दूसरा प्रकार होता है। वास्तव में , अधिकार एक वृत्ति के आधार पर विकसित हुआ जो आत्म-संरक्षण के सभी जीवित प्राणियों में आम है।

मुख्यशब्द:निजी रक्षा, आपराधिक कानून, अधिकार, सिद्धांत, आत्म-संरक्षण, कानूनी प्रणालियाँ

प्रस्तावना

मानव जाति का आवश्यक आवेग आत्म-संरक्षण है और सभी सभ्य देशों के आपराधिक कानून द्वारा इसे उचित रूप से स्वीकार किया गया है। किसी भी स्वतंत्र , लोकतांत्रिक और सभ्य राष्ट्र ने उचित सीमा के भीतर निजी सुरक्षा के अधिकार को मान्यता दी है। अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि परिस्थितियाँ मृत्यु के स्वैच्छिक कारणों से संबंधित निजी तौर पर रखे गए संरक्षण के अधिकार के कारण मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका को उचित आधार देती हैं। निजी रक्षा कानून के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जिसे धमकी दी गई हो या गिरफ्तार किया गया हो, उसे सुरक्षा के लिए आवेदन करना होगा। कानून उसे गोपनीयता सुरक्षा प्रदान करता है और उससे अपनी सुरक्षा करने की अपेक्षा करता है। जहाँ कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ निजी सुरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। वास्तविक या स्पष्ट , आसन्न जोखिम को टालने की आवश्यकता होनी चाहिए , आत्म-सुरक्षा प्राथमिक है क्योंकि , इस संबंध में , मनुष्य के लिए , या किसी जानवर या जीवित चीज़ के लिए शारीरिक कल्याण से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसलिए , मानवाधिकारों में से एक शारीरिक चोट से खुद को बचाने का अधिकार है। स्वयं की रक्षा करना बहुत सामान्य बात है; कोई खुद को मारने के बजाय मारना पसंद करेगा। निजी सुरक्षा कानून प्रारंभिक समाज की जड़ है , जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का हकदार था। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण शामिल हैं जिनमें लोगों को अपनी संपत्ति और अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। वास्तव में, यहां यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतिहास द्वारा अनुभव किए गए दो विश्व युद्ध और देशों और राष्ट्रों के समुदायों के बीच वर्तमान संघर्ष ऐसे उदाहरण हैं जहां समुदाय हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी भूमि और पानी या अन्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। राज्य द्वारा या सामाजिक हितों द्वारा मनमाने कार्यों से। आज दुनिया में हर कानूनी ढांचा हर किसी के जीवन और संपत्ति की रक्षा के अधिकार को स्वीकार करता है और उसका समर्थन करता है। एक संहिताबद्ध कानून में , उदाहरण के लिए , 1860 का भारतीय दंड संहिता , जीवन और संपत्ति की रक्षा के

लिए दूसरों के हिंसक कृत्य के खिलाफ खुद का बचाव करने के इस प्राकृतिक अधिकार को पार कर गया था।

कानूनी दार्शनिक माइकल गोर ने अपने निबंध "प्राइवेट प्रोटेक्शन" में निम्नलिखित बातें कही हैं:

"कट्टरपंथी शांतिवादियों के अलावा, व्यावहारिक रूप से हर कोई स्वीकार करता है कि ग्लेनविले विलम्स ने जिसे "निजी सुरक्षा" कहा है , वह अक्सर नैतिक रूप से स्वीकार्य है , यानी किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर (और यहां तक कि घातक) नुकसान पहुंचाना ताकि उसे या किसी निर्दोष को पीड़ित होने से रोका जा सके। समूह।"

यह उन व्यक्तियों का अस्तित्व मात्र नहीं है जो केवल मूक गवाह हैं जो निजी तौर पर संरक्षित व्यक्तियों के इस अधिकार को निरस्त करते हैं। कानून के अनुसार इसके नागरिकों को अवैध हमलों की मैन्युअल रूप से निंदा करने की आवश्यकता है। अपराधियों द्वारा धमकी दिए जाने पर सुरक्षा के अधिकार का दावा करने से पहले किसी को भी अन्य सभी विकल्पों से बचने या उन्हें ख़त्म करने की अनुमति नहीं है। मनुष्य से किसी भी समय कायर की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है , चाहे वह कितना भी कानून का पालन करने वाला क्यों न हो। किसी भी स्वतंत्र देश के लोगों में , क़ानून द्वारा स्थापित निजी वकालत के अधिकार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ख़तरे के सामने भाग जाने से बढ़कर कोई चीज़ मानवीय भावना को ख़राब नहीं कर सकती। मनुष्य पूरी तरह से न्यायसंगत है यदि वह कायम रहता है और अपने हमलावरों को जवाबी हमला करने की पेशकश करता है। हालाँकि , यह अधिकार केवल बचाव का है, दंड और प्रतिशोध का नहीं। व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियोजित बल , टाले जाने वाले या उचित रूप से पहचाने जाने वाले नुकसान के अनुपात में बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। गैरकानूनी हिंसा के खिलाफ स्वयं या दूसरों का बचाव करना कोई अपराध नहीं है , जो कानून द्वारा लगाए गए कर्तव्य के अपराधी पर मौत या गंभीर शारीरिक नुकसान या बल की उचित आशंका पैदा करता है, बशर्ते कि आवश्यक से अधिक नुकसान न हो। व्यक्तिगत रक्षा का नियम इसे व्यक्तियों के लिए उचित और उचित बनाता है। निजता के अधिकार का प्रयोग प्रतिशोधात्मक या दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं किया जाएगा। दुनिया की सभी कानूनी प्रणालियों में बल प्रयोग का सबसे प्राचीन आधार आत्मरक्षा है।

एक व्यक्ति आवश्यक बल का उपयोग करके हमलावरों के हमले की रक्षा करने का हकदार है। यह अधिकार केवल मानव शरीर की रक्षा तक ही सीमित नहीं है , बल्कि उसके रिश्तेदारों की रक्षा के लिए भी

है, शायद उस व्यक्ति की भी , जिसे किसी भीषण हमले की स्थिति में वास्तव में अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है। कानून को दूसरों की रक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि गरीबों के अत्यधिक दुर्व्यवहार में प्रबुद्ध उचित आक्रोश निश्चित रूप से एक महान प्रेरणा है। यह लोगों को अपने व्यक्तिगत जोखिमों को भूलने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में मदद करता है। कानून को सावधान रहना चाहिए कि वह साहस और मानवता के बीच के संबंधों को ढीला न करे जो इस उदार साझेदारी को बनाते हैं। यह उसे, जो लोगों के हितों की रक्षा करता है, सारा सम्मान और पुरस्कार प्रदान करे। निजता का अधिकार किसी के व्यक्ति, आवास या संपत्ति को उस हमलावर से बचाने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है जो स्पष्ट रूप से इसे छीनने का इरादा रखता है और चाहता है। व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के लिए निजता का अधिकार आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें अवैध हमलों को खत्म करने के लिए राज्य सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और कोई भी राज्य , चाहे कितना भी बड़ा सहारा क्यों न हो , पुलिस अधिकारी को प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को ट्रैक करने और अपराधी के खिलाफ सुरक्षा करने की जिम्मेदारी से वंचित नहीं कर सकता है। कार्यवाही करना। चैंबर्स इंग्लिश डिक्शनरी "निजी सुरक्षा" को किसी के स्वयं के व्यक्ति की सुरक्षा के रूप में परिभाषित करती है ; अधिकार आदि। निजी रक्षा के बजाय यह "आत्मरक्षा" शब्द का उपयोग करता है। चैंबर्स इंग्लिश डिक्शनरी इसका वर्णन "निजी सुरक्षा" के रूप में करती है। यह निजी सुरक्षा की सबसे शाब्दिक परिभाषा है , यानी किसी के जन्म के अधिकार की रक्षा में कोई भी कार्य। इस मामले में अधिकार मनुष्य के अधिकार पर लागू होता है। बी.सी. कर्ज़न ने निजी रक्षा का वर्णन इस प्रकार किया है: "यदि कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा या अपनी संपत्ति में कोई अपकृत्य करता है , तो आचरण उचित परिस्थितियों में होने पर वह व्यक्ति वास्तव में ज़िम्मेदार नहीं है।" ओसबोर्न के सक्सिन्ट लॉ डिक्शनरी ऑफ प्राइवेट प्रोटेक्शन में एक अन्य अवधारणा का वर्णन है:" व्यक्ति या संपत्ति की निष्पक्ष रक्षा में की गई कार्रवाई। आड़ के तौर पर इसे गर्भपात का नाम दिया जा सकता है। किसी के परिवार और संभावित रूप से हर दूसरे नागरिक की गोपनीयता के अधिकार को अवैध बल द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए"।

आत्मरक्षा की अवधारणा

आत्मरक्षा की जटिल परिभाषा एक है। यह देश-दर-देश और समय-समय पर विशेष घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों में , आत्मरक्षा की अवधारणा नाटकीय रूप से विकसित हुई है। आत्मरक्षा के मामलों में किसी व्यक्ति को इस तरह फाँसी दी जाती थी मानो उसने पहले कोई गंभीर

कृत्य किया हो क्योंकि यह हत्या उचित नहीं थी। संकेतित समूह के पास जूरी को बरी करने का अधिकार नहीं था। प्रारंभिक अंग्रेजी आम कानून ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि आत्मरक्षा में की गई हत्या , हत्या पर लगे दोष को हटा देती है। उस समय , अपराध दायित्व का अपवाद एक भ्रांति थी। अंग्रेजी में यह बात समझ में नहीं आती थी कि हत्या करना आत्मरक्षा के लिए की गई हत्या है। यह धारणा कि हमलावर वह पार्टी है जो युद्ध के लिए जिम्मेदार है , यानी कि पार्टी नैतिक रूप से रक्षक के हितों को खतरे में डालने की प्रभारी है , आंदोलनकारी और रक्षकों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण निजी सुरक्षा बदल गई। हालाँकि , रक्षा शक्तियाँ निष्पक्ष और खतरे के अनुपात में होनी चाहिए। आक्रामक को संतुलन चरण को कम मानने का अधिकार है। एक छोटे से परिणाम से बचने के लिए घातक बल का प्रयोग करना शायद ही कभी उचित होता है। दूसरे शब्दों में , बचावकर्ता का आचरण , जो स्वयं का अपराध हो सकता है , उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि वह हमले के खिलाफ खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है। वह स्पष्ट रूप से खतरे के प्रति आनुपातिक है और इसलिए अस्वीकार्य है। निजी रक्षा के मामले में कानून दो बुराइयों में से कम बुराई को ध्यान में रखता है। यह एक अपराधी से सार्वजनिक शांति और कानूनी व्यवस्था की सुरक्षा के अनुरूप , रक्षक के वैध हितों की रक्षा करने की आवश्यकता का एक कारण भी है। कल्याणकारी राज्य और समाज की सुरक्षा, व्यक्ति के व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब राज्य ने अपने ऊपर ले ली है। यहां तक कि न्यायपालिका ने भी आत्मरक्षा के संवैधानिक अधिकार को स्वीकार किया और , आपराधिक संहिता के अपनाए गए विधायी प्रावधानों द्वारा; विधायिका ने इसे कानूनी संरक्षण भी दिया।

आत्मरक्षा के अधिकार का आधार

यह एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है जो किसी भी जानवर के साथ समान रूप से अपनी रक्षा करने की है। जैसा कि बी ने दिखाया है. पार्के: 'प्रकृति लोगों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए इतनी ताकत का उपयोग करके उनकी रक्षा करती है। ' अनिवार्य रूप से, निजी सुरक्षा के अधिकार को किस हद तक स्वीकार किया जाता है यह राज्य की अपनी प्रजा की रक्षा करने की इच्छा और संसाधनों पर निर्भर करता है। इसलिए, अशांत आबादी का अपनी रक्षा का अधिकार अधिक है।

निजी रक्षा का अधिकार लोगों के लिए नाजायज हमलों के प्रभावी प्रतिरोध द्वारा अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का एक अत्यधिक सम्मानित अधिकार है। निजता के सिद्धांत के पीछे मूल अवधारणा यह है कि यदि कोई व्यक्ति या उसकी संपत्ति खतरे में है और राज्य के उपकरणों से तत्काल सहायता आसानी से

उपलब्ध नहीं है , तो उसे आत्म-सुरक्षा और खुद की और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है। कानून प्रत्येक व्यक्ति को मैन्युअल रूप से आक्रामकता का विरोध करने का प्रावधान करता है। जब उस पर अपराधियों द्वारा हमला किया जाता है , तो किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जाती है। निजता के अपने अधिकार का प्रयोग करने से पहले उन्हें कोई अन्य उपाय नहीं करना चाहिए। दरअसल , किसी भी स्वतंत्र देश के लोगों में निजी सुरक्षा के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए। निजी सुरक्षा के सिद्धांत में, यह बताना महत्वपूर्ण है कि जिस हिंसा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा करने की अनुमति है, वह क्षति के कानूनी रूप से स्वीकार्य उद्देश्यों से अधिक नहीं है जिसे रोका जाना चाहिए या उचित रूप से पकड़ा गया. निजी सुरक्षा विशेषाधिकार कभी भी प्रतिशोधात्मक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होने चाहिए। कानून में ऐसे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जिसकी संपत्ति को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा हो और उल्लंघनकर्ताओं द्वारा अधिकारियों की सुरक्षा की मांग की जा रही हो। निजी सुरक्षा अधिकारों का एक सामाजिक कार्य है , और उन्हें उदार तरीके से देखा जाना चाहिए। ऐसा अधिकार न केवल बुरे कर्ताओं को सीमित करेगा , बल्कि यह एक स्वतंत्र नागरिक की अच्छी आत्माओं को विकसित करेगा। ख़तरे के सामने भाग जाने से बढ़कर कोई चीज़ मानवीय भावना को ख़राब नहीं कर सकती। केवल आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने के लिए निजी सुरक्षा के विशेषाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार का दावा किया गया है उसकी निजी तौर पर सुरक्षा करने का अधिकार हमला या हिंसा को दर्शाता है। यदि हमला करने वाला व्यक्ति हमलावर नहीं है , तो पीड़ित निजी सुरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। प्रतिवादी हमले को भड़काने के लिए आत्मरक्षा को एक रणनीति या बहाने के रूप में उपयोग नहीं करता है ताकि हमलावर रुक जाए और फिर आत्मरक्षा छूट के लिए आवेदन करे।

निजी सुरक्षा के पीछे सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को अपने ऊपर निर्देशित बल के गैरकानूनी उपयोग से बचाने के लिए उचित बल का उपयोग करना वैध है। इस तरह के निजी रक्षात्मक अभ्यास को विफल किए जाने वाले खतरे की भयावहता के अनुपात में होना चाहिए। निजी सुरक्षा और आवश्यकता के सिद्धांत के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। जहां सुरक्षा का अधिकार आवश्यकता से उत्पन्न होता है , वहीं दूसरा व्यापक है और सभी स्थितियों में आत्मरक्षा नहीं हो सकती। आधुनिक न्यायशास्त्र में , "आवश्यकता का कोई क़ानून नहीं होता" कहावत का कोई स्थान नहीं है। कानून की नीति के रूप में राज्य कुछ परिस्थितियों को मान्यता देता है जो बाहरी हैं और स्व-निर्मित नहीं हैं बल्कि कुछ अंतरराष्ट्रीय मूल से आती

हैं और तथाकथित अपराध के लिए अग्रणी बाहरी बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण आरोपी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करता है। कानून इस तरह के बाहरी दबाव को मान्यता नहीं देता है और पाता है कि यह कृत्य क्षमा योग्य है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों और संपत्ति को नुकसान से बचाए। फिर भी, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी यदि सार्वजनिक सहायता उपलब्ध नहीं है और कोई व्यक्ति या उसकी संपत्ति आसन्न खतरे में है। ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति या संपत्ति को तुरंत धमकी देने से रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। यह निजी रक्षा का विशेषाधिकार है. हालाँकि ऐसा कोई विशेषाधिकार मौजूद नहीं है और यह कुछ सीमाओं के अधीन है। अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करते हुए निजी सुरक्षा का अधिकार लोक सेवकों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति केवल उचित शक्ति का उपयोग कर सकता है ; यह ताकत आसन्न जोखिम के बराबर है.

आत्मरक्षा की कानूनी अवधारणा

बल जो शारीरिक चोट, संपार्श्विक क्षति या यहां तक कि मौत का कारण बनता है उसे उचित या माफ किया जा सकता है, क्योंकि बल का उपयोग सार्वजनिक या निजी हितों की रक्षा के लिए वैध रूप से किया गया है। इसलिए, किसी भी अपराध का सामान्य बचाव, जो बल के उपयोग का एक हिस्सा है या बल के उपयोग द्वारा किए जाने का दावा किया गया है , सार्वजनिक और निजी है। "वैधानिक रूप से" शब्द का असंवैधानिक उपयोग सामान्य सुरक्षा की उपस्थिति को पुनर्स्थापित करता है , हालांकि यह तब तक लागू होता है , जब तक कि स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ा न जाए , भले ही क़ानून को इसकी आवश्यकता हो या नहीं। यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक या निजी बचाव बयानों को अस्वीकार करने के लिए अदालत उत्तरदायी है। किसी व्यक्ति का विरोध किया जाना आम बात है और उसका प्रतिरोध अवैध नहीं होगा। जब तक कि वह वास्तव में मारा न जाए तब तक इंतजार करना जरूरी नहीं है , यदि एक पक्ष आत्मरक्षा में हमला करने से पहले अपना खतरनाक हाथ उठाता है जिस पर दूसरा हमला कर सकता है। न ही सुरक्षा अधिकार हमले के अधीन व्यक्ति तक ही सीमित है ; इनमें वे सभी लोग शामिल हैं जो किसी न किसी कर्तव्य के अधीन हैं - हालांकि केवल सामाजिक और कानूनी नहीं - उसकी रक्षा करने के लिए , उदाहरण के तौर पर पुराने अधिकारियों द्वारा एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है , अपने पिता के बच्चे की रक्षा करता है , अपने नौकर की रक्षा करता है , या अपने नौकर की रक्षा करता है मालिक। हालाँकि , ब्लैकस्टोन ने कहा कि यह बहुत व्यापक था और गलतफहमी पर केंद्रित था ; इस प्रकार की हत्या को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब हमले का स्वयं ने विरोध किया हो और इस प्रकार , हत्या को

इस तथ्य से उचित ठहराया जा सकता है कि वे एक बड़े अपराध से बचने के लिए प्रभावित हुए थे , मामले को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह ऐतिहासिक रूप से सच है , क्योंकि प्रारंभिक कानून में की गई हत्या "क्षम्य" थी और "उचित नहीं थी।" इस प्रकार आत्मरक्षा में हत्या को सख्त कर्तव्य के पुराने कानून में पकड़ लिया गया और केवल राजा की कृपा से ही हत्यारे को बख्शा जा सकता था। आत्मरक्षा में हत्या की याचिका को उचित ठहराने के लिए , स्कॉटलैंड में उच्च न्यायालय ने यह आवश्यक पाया है कि अभियुक्त की मौत का घातक विरोध किया जाना चाहिए था।

हॉकिन्स ने एक व्यक्ति की परिस्थितियों की पहचान की है और हत्या के लिए पूर्ण आत्मरक्षा का आरोप लगाया है। इसमें किसी अन्य को लूटने या घर में उसे मारने के प्रयास में किसी व्यक्ति की हत्या करना भी शामिल था। यह बचाव परिवार के किसी सदस्य या हमलावर व्यक्ति के नौकर या गृहस्वामी के कार्यों पर लागू किया गया था।

हेल ने स्वीकार किया कि यदि किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ कोई हिंसक अपराध किया गया हो तो आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत किसी व्यक्ति की जान को खतरे में डालने वाले तरीके से हत्या की अनुमति है। केवल एक व्यक्ति जिस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से हमला किया गया है , जिसके पास शारीरिक नुकसान से बचाने के लिए कानून का सहारा लेने की क्षमता नहीं है , उसे तर्कसंगत कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए। नागरिकों के ख़िलाफ़ हत्या और मानव वध जैसे अपराधों के ख़िलाफ़ उनका पूरा बचाव था क्योंकि उनके कार्य निष्पक्ष थे। उसके बारे में कहा गया था कि जब उसने आत्मरक्षा में काम किया तो उसे उचित ठहराया गया, ताकि उस पर किसी गलत काम का आरोप न लगे , खुद को शामिल न किया जाए या दूसरे व्यक्ति को यह नुकसान पहुंचाने का प्रयास न किया जाए। ऐसा तर्क दिया जाता है कि किया गया कार्य रक्षात्मक होना चाहिए न कि आक्रामक। केवल सुरक्षा और रोकथाम की सीमा को पार नहीं किया जाना चाहिए। आत्मरक्षा कानून इस निष्पक्ष विश्वास के साथ किए गए कार्य को माफ करता है कि कोई आसन्न खतरा है और यदि इस अनुमान में प्रतिवादी को चोट लगती है , तो उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए बंदूक लेकर जा रहा है , तो इच्छित पीड़ित आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का हकदार है। यह अधिनियम आत्मरक्षा में रचनात्मक और विचारशील है। "आकस्मिक आत्मरक्षा" की एक विसंगतिपूर्ण अवधारणा की कोई समझ नहीं है। यह स्पष्ट है कि निजी रक्षा में सन्निहित अधिकार दूसरों के हिंसक व्यवहार को प्रतिबंधित करने के लिए तर्क , तर्क और विवेक की आवश्यकता है जो एक व्यक्ति उस पर थोपना जानता है। यह बहुत ही सरल है। हो सकता है कि कोई

हत्या करना चाहे और फिर भी दोषी हो। अदालतों को परिस्थितियों और आत्मरक्षा के अधिकार की गुहार लगाने वाले व्यक्ति के जीवन या संपत्ति के आसन्न खतरे और निर्णय लेते समय आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए बल को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट मामले पर विचार कर सकता है. इस अधिकार के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना भी अभियुक्त का कर्तव्य है।

भारत में निजी रक्षा

भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 में, भारत में शरीर और संपत्ति की सुरक्षा पर निजी कानून शायद इस आधार पर आधारित है कि आत्म-संरक्षण का अधिकार एक मौलिक मानवीय प्रवृत्ति है। "सामान्य अपवाद" लोगों की सुरक्षा के अधिकार की एक अभिन्न वैधानिक संरचना है, साथ ही वे सीमाएं भी हैं जिनके भीतर आत्म-सुरक्षा के अधिकार के मुद्दे , दायरे और सीमा से निपटने के लिए अधिकार का अभ्यास किया जाना चाहिए। भारत में। ये धाराएँ अपने आप में परिपूर्ण हैं , और इन्हें आम कानून के तहत आत्मरक्षा के अधिकार को विनियमित करने वाले सिद्धांतों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है।

भारत में प्रयुक्त "निजी सुरक्षा" शब्द भारतीय दंड संहिता में निर्दिष्ट नहीं था। न्यायपालिका को किसी औपचारिक अर्थ के अभाव में उन शब्दों की रूपरेखा का वर्णन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत में, निजी सुरक्षा का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है , जिसके लिए यदि अनुरोध नहीं किया गया तो यह एक अपराध होगा। यह ऐसे कार्य के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है जिसे अन्यथा अपराध के रूप में देखा जाएगा। दूसरे शब्दों में , आपराधिक दायित्व से छूट स्थापित की गई है। भारतीय दंड संहिता में पाया गया गोपनीयता कानून अंग्रेजी कानून पर आधारित है और इसे मामूली संशोधनों के साथ देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 भारत में प्रशासित निकायों और संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 और 106 , जो अदालतों को यह निर्धारित करने में सहायता करती हैं कि कानून में अपराध किया गया है या नहीं , और क्या आरोपी को बरी किया जाना चाहिए या दंडित किया जाना चाहिए। विधि आयुक्तों के अनुसार , इन धाराओं द्वारा निर्धारित सिद्धांत को इस मामले में एक मूर्खतापूर्ण परीक्षण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लॉ कमिश्नर्स ने कहा कि, हालांकि हमारा मानना है कि यह दावा करना सही है कि हम कोड के हिस्से से कम खुश नहीं हैं, लेकिन यह मौजूद

है। हमें सावधानी या इलाज की कोई जरूरत नहीं बताई जा सकती. हमारे काम के किसी भी हिस्से के कारण हमें अधिक तनाव नहीं हुआ , या अधिक बार दोबारा लिखा गया। हालाँकि हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि हम इसे हमेशा अत्यंत अपूर्ण स्थिति में छोड़ रहे हैं; और जबकि यह निश्चित रूप से हमसे बहुत बेहतर है, हमारा मानना है कि यह अभी भी किसी भी आपराधिक कानून प्रणाली के सबसे कम विस्तृत अनुभागों में से एक होना चाहिए।

नारायण सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार मुख्य रूप से कानून, यानी आईपीसी तक सीमित सुरक्षात्मक अधिकार है। यह एक सुरक्षा अधिकार है, दंड नहीं, जिसे गैरकानूनी हिंसा को रोकना चाहिए , न कि दंडात्मक उपाय। इसे प्रतिशोधात्मक , अपमानजनक या आक्रामक इरादे के लिए आड़ नहीं कहा जा सकता। भारतीय दंड संहिता में , इस बात का ध्यान रखा गया कि ऐसी कोई विधि शामिल न की जाए और न ही स्थापित की जाए जिसके द्वारा किसी हमले पर हत्या का दावा किया जा सके , हालांकि इसमें कानून के अभ्यास का प्रावधान किया गया था। रक्षा के अधिकार में , विशेषकर यदि रक्षा कायम नहीं है, आक्रामक शुरुआत करने का अधिकार शामिल नहीं है।

यदि किसी अपराध के घटित होने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है , तो निजी सुरक्षा के अधिकार का कोई लाभ नहीं होगा। इस अधिकार को केवल इसलिए लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसने असंवैधानिक या असंवैधानिक कार्य किया है। भारत में , निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग केवल गैरकानूनी हिंसा को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है , न कि प्रतिशोध के लिए। यह अपराध चोरी , बर्बरता या आपराधिक उल्लंघन जैसा अपराध नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में , निजता का अधिकार एक सुरक्षा है न कि कोई आवश्यकता या दमनकारी तंत्र। अभियुक्त को यह तर्क नहीं देना होगा कि उसने निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 97 की शर्तों को किसी याचिका या निजी बचाव के लिए संदर्भित किया जाता है , तो अदालत उसके समक्ष तथ्यों और जानकारी के मद्देनजर इसकी जांच करने के लिए बाध्य है। अभियुक्त को अपराध के लिए तभी दोषी पाया जा सकता है जब दलील नहीं दी गई हो। निजता का अधिकार केवल उसी व्यक्ति के लिए सुलभ है जो किसी आसन्न जोखिम को उत्पन्न होने से रोकने की तत्काल आवश्यकता का सामना करता है। आवश्यकता पूरी करने के लिए आरोपी को सीमा से आगे नहीं जाना चाहिए।

निजता के अधिकार पर नियम धारा 96 में दिया गया है जो घोषित करता है कि "निजता के अधिकार के प्रयोग में कोई अपराध नहीं किया गया है ;" जबकि अनुच्छेद 97 , जो शरीर और संपत्ति के निजी सुरक्षा अधिकार के विषयों से संबंधित है और निजी सुरक्षा के अधिकार के पैमाने को निर्धारित करता है , कहता है कि हर कोई प्रतिबंधों के अधीन है। धारा 96 में कहा गया है कि धारा 99 उस स्थिति का वर्णन करती है जिसमें कोई व्यक्ति निजी तौर पर व्यवसाय और संपत्ति दोनों की रक्षा करने का हकदार नहीं है। यह अधिकार की सीमाएँ निर्धारित करता है। धारा 102 और 105 क्रमशः निजी निकाय और संपत्ति के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता को संबोधित करते हैं , जबकि चोट की सीमा , जिसमें स्वैच्छिक मृत्यु भी शामिल है, इस हद तक कि इसके अभ्यास में अपराधी को भी लगाया जा सकता है। शरीर और संपत्ति के अधिकार, धारा 100, 101, 103 और 104 द्वारा संरक्षित हैं। धारा 98 उन व्यक्तियों के खिलाफ निजी सुरक्षात्मक सुरक्षा प्रदान करती है जो गर्भावस्था , पागलपन, लापरवाही या गलत धारणाओं के कारण अपराध करने के लिए वैध रूप से अयोग्य हैं। दूसरे शब्दों में , यह उन लोगों के कार्यों को निजी तौर पर सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है जिनके हितों को सजा से बाहर रखा गया है। धारा 106 में एक व्यक्ति को निजी सुरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए खुद को नैतिक क्षति से बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को घायल करने का जोखिम उठाने की भी आवश्यकता होती है। तदनुसार, अनुच्छेद 96 में सामान्य तौर पर कहा गया है कि कुछ भी निजी सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है। दाईं ओर की रूपरेखा को बाद की धारा 97-98 और 100-106 के तहत संबोधित किया गया है और विस्तृत सीमाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 99 में उल्लिखित सीमाएँ या सीमाएँ इन भागों में वर्णित सभी अधिकारों तक विस्तारित हैं।

आत्म-संरक्षण और आत्म-रक्षा

आत्म-सुरक्षा की परिभाषा आत्म-सुरक्षा पर आधारित है। किसी भी जीवित प्राणी की मूल प्रवृत्ति आत्म-संरक्षण है। इसका उपयोग प्राकृतिक और भौतिक शक्तियों के विरुद्ध किया जाता था और आत्मरक्षा का उपयोग अब मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं के विरुद्ध किया जाता है। यह इंसानों और जानवरों दोनों में मौजूद होता है। यह जीवन की लड़ाई पर आधारित है। स्वयं को सहारा देने और संरक्षित करने के लिए ही हम खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं। जब जीवित प्राणी को अपनी जलवायु के भीतर आत्म-संरक्षण प्राप्त होता है , तब भी उसके विरुद्ध लड़ने के लिए भौतिक और बाहरी ताकतें मौजूद रहती हैं , और इन आवश्यकताओं में से एक की परिकल्पना निजी सुरक्षा के अधिकार द्वारा की जाती है। इसलिए , किसी की

रक्षा करने की इच्छा आत्मरक्षा के विचार को जन्म देती है। इसे आवश्यकता के कारण किसी अन्य व्यक्ति को अपंग बनाना या हत्या करना कहा जा सकता है , जब कोई व्यक्ति खुद के लिए या किसी और के लिए आसन्न खतरे की स्थिति में हो और जब अपनी जान बचाने या बचाने के लिए हमला करना उचित समझा जाता हो। उसकी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान से बचाना। परिणामस्वरूप , प्रकृति का नियम चोरी, हत्या, आगजनी, धूप आदि जैसे हिंसक या नृशंस अपराधों से बचकर हत्या को माफ कर देता है। इस अर्थ में , मानव-मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि यह आत्मरक्षा में मानव जीवन लेने का एक नेक, जानबूझकर किया गया कार्य है, यह सामान्य ज्ञान है कि मनुष्य कभी-कभी किसी पूर्व परिस्थिति या दृढ़ विश्वास से उत्पन्न अनैच्छिक प्रतिबिंब में कार्य करते हैं , भले ही वे कार्रवाई के क्षण में पूरी तरह से अनजान हों विशिष्ट कार्रवाई और बाद में इसके बारे में पता नहीं चलता।

निष्कर्ष

आत्मरक्षा का अधिकार ईश्वर द्वारा दिया गया अधिकार है, जो मानव कानून के अधीन या उसके द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है , यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं है , तो यह ज्ञात है: "होना या न होना ही समस्या है।" जीवन के अधिकार में उस अस्तित्व को सुरक्षित रखने का अधिकार है। समाज के विकास और प्रगति पर शोध करने पर हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में जब समाज की आधुनिक समझ विकसित नहीं हुई थी और लोग प्रकृति की स्थिति में मौजूद थे, तब वह अपनी समस्याओं को उसी हद तक ठीक करते थे, जिस हद तक वे कर सकते थे। प्रचलित कानून था 'शक्ति सही है।' अंतिम परिणाम यह हुआ कि ताकतवर गरीबों पर हावी हो गया और अक्सर अच्छे लोगों की सर्वोच्चता गलत थी और इसलिए असमानता, अराजकता और अव्यवस्था के परिणाम सामने आए। नैतिक अर्थों में समाज में क्रमिक वृद्धि के साथ निजी अधिकारों को संरक्षित करने का कार्य तब समाज या राज्य को दिया गया। राज्य इस भूमिका को किस हद तक निभाएगा यह इस कार्य को करने की राज्य की क्षमता और संसाधनों पर निर्भर करता है। हालाँकि, यह मामला बना हुआ है कि समाज कभी भी हर समय और सभी मामलों में सभी का समर्थन करने के लिए समन्वित और साधन संपन्न नहीं होगा। जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में राज्य की अक्षमता राज्य को उन मामलों में किसी भी नागरिक के अधिकार की अनुमति देने के लिए बाध्य करती है जहां हिंसा का विरोध करने या हिंसा को हिंसा से दूर करने के लिए कुछ सीमाओं के भीतर राज्य सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है। यह स्पष्ट है कि आत्मरक्षा के अधिकार से जुड़े दो प्रमुख कारक हैं: पहला यह कि निजी लोगों को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज का प्राथमिक कर्तव्य लेने में सक्षम नहीं

होना चाहिए और दूसरा , इसके लिए कोई तंत्र होना चाहिए। हर समय और हर स्थिति में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए। इन सिद्धांतों के अनुसार राज्य को उन मामलों में आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है जहां वह बचाव नहीं कर सकता है , लेकिन जिन मामलों में वह बचाव कर सकता है, वह इस अधिकार से इंकार कर देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अभिमन्यु कुमार , "कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व" , सामाजिक विज्ञान अनुसंधान नेटवर्क , 11 अगस्त 2009।

2. अल्बर्ट अल्चुलर, "निगमों की सजा के बारे में सोचने के दो तरीके", 46 पूर्वाह्न, क्रिम, एल. रेव, 2009।

3. आनंद, अभिषेक. "निगमों को उनके आपराधिक कृत्यों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना: एक तर्क"। 01(03), कंपनी लॉ जर्नल 2004।

4. एंड्रयू वीसमैना , "कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व के लिए एक नया दृष्टिकोण" , खंड, 44, अमेरिकी आपराधिक कानून समीक्षा 2007।

5. अंगिरा सिंघवी , "भारत में कॉर्पोरेट अपराध और सजा: कानून में आवश्यक संशोधन" , खंड, 1, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस साइंसेज, 2006।

6. अर्लेन "कॉर्पोरेट आपराधिक कानून के संभावित विकृत प्रभाव" खंड , 23 जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज , 1994।

7. बौध, सुमित, "कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व: टाटा उल्फा सांठगांठ के प्रकाश में एक समीक्षा। छात्र बार समीक्षा (छात्र अधिवक्ता) 10(1), 1998।

8. भारमगौड़ा रतन आर. "कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व: एक अवलोकन" , खंड, 2, कोचीन यूनिवर्सिटी लॉ रिव्यू, 2003।

9. भट्ट, बिमल आर. "स्वतंत्र निदेशक-वास्तव में एक कॉर्पोरेट कार्यवाहक" सेबी और कॉर्पोरेट कानून , 90, 2009।

10. ब्रैंडन एल. गैरेट, "वैश्वीकृत कॉर्पोरेट अभियोजन", खंड, 97, वर्जिनल लॉ रिव्यू, 2011।

11. कार्लोस गोम्स-जारा डाइज़, "21वीं सदी में कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व: क्या सभी निगम गलत काम करने में समान रूप से सक्षम हैं?" खंड, 41, स्टेटसन लॉ रिव्यू 2011।

12. चंद्रा, निखिल, ई. संपता, पूर्णिमा "कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयर धारकों का हित - लिस्टिंग समझौते के खंड 49 का आकलन", 30(1- 8), सेबी और कॉर्पोरेट कानून। 2001.

13. चंद्रात्रे, के.आर. "कंपनियों द्वारा अपराधों के लिए निदेशकों की विचित्र देनदारी-मानक दंड प्रावधान का एक गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन", 02(03), कॉर्पोरेट कानून मामले 2000।

14. चार्ल्स एल. हॉवर्ड और थॉमस फ़र्टोडो , "द यूनाइटेड स्टेट्स सेंटेंसिंग गाइडलाइन्स" , द ओम्बड्समैन एसोसिएशन सुइट टेक्सास, जून 1998।

15. चोखानी, प्रदीप, "भारत में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अधिनियम-एक सिंहावलोकन", 88, सेबी और कॉर्पोरेट कानून, 2008।